of the India-pakistan maritime boundary from seawards by commencing at the Exclusive Economic Zone limit and proceeding landwards could be considered. It has- been agreed to continue discussions on the subject.

Pakistan has also consistently sought to internationalise India-Pakistan bilateral issues. Both countries are committed under the Simla Agreement to resolve all issues peacefully through direct bilateral negotiations. This has been recognised by the international community. Government have made it clear that there is no place for any third party involvement of any kind whatsoever in India-Pakistan bilateral relations.

Progress in Indo-US Negotiations

569. DR. MANMOHAN SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what progress has been made in the Indo-USA negotiations for resolving the issues arising out of the Pokhran-2 tests;

(b) whether Government have set any time table to resolve the remaining issues; and

(c) what will be the beneficial impact on Indian economy of relaxation of sanctions recently announced by the Government of the United States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) and (b) The negotiations between US and India are aimed at narrowing gaps of perception. Seven rounds of discussions have so far been held. On November 7, the US administration announced a partial lifting of unilateral restrictive meausres. The dialogue which is being held in a friendly and frank atmosphere is continuing and no time frames have been set. The objective is not only to safeguard India's legitimate security interests, but also to lay a firm foundation for further exchanges and cooperation between the two countries.

(c) The partial lifting of restrictive economic measures by the United States Government as announced is likely to help improve the climate for mutually beneficial interaction between US and Indian business concerns.

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय भाषाएं

570. **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण अफ्रीका में डरबन विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा विभाग को बदं कर दिया गया हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि दक्षिण अफ्रीका सरकार अपने देश के विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में भी तमिल, तेलुगु, हिन्दी, उर्दू और गुजराती जैसी भारतीय भाषाओं के अध्ययन को बदं करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार ने ऐसी स्थिति पैदा न होने देने के लिए क्या कार्रवाई की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) हमें डरबन वेस्टविले विद्यविद्यालय और प्रान्तीय शिक्षा विभाग से भारतीय भाषाओं के अध्ययन को फिर शुरू करने के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) इस संबंध में भारत सरकार गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें हुए हैं।

दलाई लामा से बातचीत

571. **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ दिनों में प्रधान मंत्री और दलाई लामा के बीच बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है, कि चीन ने इस बातचीत पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और

(घ) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) सन्त दलाई लामा ने 15 अक्तूबर, 1998 को प्रधान मंत्री के साथ शिष्टाचार मुलाकात की।

(ग) और (घ) 22 अक्तूबर, 1998 के वक्तव्य में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसे चीन के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप की संज्ञा दी और इसके प्रति गहरा रोष प्रकट किया तथा इस मुलाकात पर खेद व्यक्त किया। इसके प्रत्युत्तर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन की प्रतिक्रिया न्यायोचित नहीं है और यह बताया कि सन्त दलाई लामा का उत्तरोत्तर भारतीय प्रधानमंत्रियों द्वारा एक श्रद्धेय आध्यात्मिक तथा धार्मिक मान्य के रूप में उनकी हैसियत के अनुसार सत्कार किया गया।

Extradition of Qucttrachi

572. SHRI KULDIP NAYYAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to ask for the extradition of Quettrachi, an Italian national, who has been identified as one of the guilty parties in the Bofors gun kickback scandal; and

(b) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) and (b) The investigation of the Bofors case is continuing. Formal extradition request at this stage is premature.

Hotline between India and Pakistan

573. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether nuclear experts from 15 countries gathered in Hiroshima mooted a proposal to open up a hotline between India and Pakistan to ease tension heightened by their nuclear tests alongwith other disarmament proposals;

(b) if so, the details thereof;

(c) the reaction of India and Pakistan to the proposals mooted; and

(d) details of fresh initiatives taken to ease tension generated after recent nuclear tests'?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) and (b) Yes, Sir, Government have seen reports of a call made by experts from 15 countries gathered in Hiroshima for the "Emergency Action Conference" on August 30-31, 1998. The objective of the conference hosted by Japan was to make recommendations on nuclear non-proliferation and disarmament.

(c) and (d) Hotlines between India and Pakistan already exist. During the recent bilateral talks between the two countries at Islamabad on October 16-18, apart from other proposals on confidence building, a proposal was also made to upgrade and enhance the existing communication links.

विखण्डनीय सामग्री के उत्पादन पर रोक

574. **श्री चीमनभाई हीराभाई शुक्ला :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य यूरोपीय देशों को विखण्डनीय सामग्री के उत्पादन पर एक पक्षीय प्रतिबन्ध के संबंध में भारत के दृष्टिकोण से अवगत कराया है,

(ख) क्या पोखरण परमाणु के बाद अमरीका तथा उनके सहयोगी यूरोपीय देशों ने भारत के साथ व्यापार के आदान-प्रदान पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इसके क्या कारण है, और

(घ) क्या सरकार इस निर्णय की समीक्षा करने का विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) सरकार ने घोषणा की है कि भारत एक ऐसी भेदभाव रहित, बहुपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय रूप से एव प्रभावशाली ढंग से समर्थनीय संधि की बातचीत मे रचनात्मक भागीदारी निभाएगा जिससे भविष्य में नाभिकीय शस्त्रों अथवा अन्य नाभिकीय विस्फोटक यंत्रों के विखण्डनीय सामग्री के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। भारत जेनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में बातचीत की प्रक्रिया के दौरान इस क्षेत्र में किसी भी अन्य बहुपक्षीय पहलकदमियों पर गंभीरता से गौर करेगा।